भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 740
(दिनांक 04.02.2026 को उत्तर देने के लिए)

भारत में सामुदायिक रेडियो मुहिम को सहायता

740. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः

श्री प्रदीप कुमार सिंहः

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः

श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः

श्री अनन्त नायकः

श्री बंटी विवेक साहूः

श्री नव चरण माझीः

श्री महेश कश्यपः

श्री भोजराज नागः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या सरकार ने 'भारत में सामुदायिक रेडियो मुहिम को सहायता' योजना के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय और प्रौद्योगिकीय सहायता के ग्रामीण, जनजातीय और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन-संपर्क पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है और विशेषकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों, विशेषकर छिंदवाड़ा और आसपास के जनजाति बहुल क्षेत्रों में संचालित स्टेशनों द्वारा प्रसारण, वित्तीय संसाधनों, मानव संसाधनों और तकनीकी संचालन से संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या स्थानीय युवाओं, महिला समूहों और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी बढ़ाकर स्थानीय विकास और सामाजिक लामबंदी के साधन के रूप में सामुदायिक रेडियो की दीर्घकालिक

व्यवहार्यता सुनिश्चित करने और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई उपाय विचाराधीन हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): सरकार सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) को प्रसारण एवं स्टूडियो उपकरणों की खरीद, प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों, तकनीकी मार्गदर्शन (हैंडहोल्डिंग) तथा सामग्री विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके लिए सरकार 'भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान को सहायता' नामक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है, ताकि मौजूदा सीआरएस को सुदृढ़ करना तथा नए सीआरएस की स्थापना करना सुनिश्चित किया जा सके। सीआरएस को तकनीकी सहयोग प्रदान करने और उनकी क्षमता वृद्धि को सुगम बनाने के लिए सरकार देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करती है।

मध्य प्रदेश में मंत्रालय द्वारा वित्तीय अनुदान के माध्यम से 17 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को सहायता प्रदान की गई है। इस मंत्रालय को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से किसी भी सामुदायिक रेडियो स्टेशन से वित्तीय सहायता संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकार स्कीम के अंतर्गत वित्तीय एवं प्रौद्योगिकी सहायता के प्रभाव का नियमित रूप से आकलन करती है, जिसके लिए आवधिक निगरानी, उपयोगिता रिपोर्ट, निरीक्षण तथा तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किए जाते हैं। इस स्कीम से ग्रामीण, जनजातीय तथा वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीयकृत सामग्री, सामुदायिक सहभागिता तथा क्षमता निर्माण द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की कम से कम 50 प्रतिशत सामग्री का निर्माण अनिवार्य रूप से सामुदायिक सहभागिता के साथ तैयार किया जाता है, जिसमें से ऐसी कम से कम आधी सामग्री महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित होती है।

******